अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया के समक्ष

मूर्ति श्री रघुनाथ जी अपीलकर्ता
बनाम

जोगिंदर सिंह और अन्य प्रतिवादी

1967 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 290

16 दिसंबर 1968

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI)-धारा 6-पंजीकृत सोसायटी, एक संकल्प द्वारा, सोसायटी की ओर से मुकदमा दायर करने के लिए अपने अध्यक्ष और सचिव को अधिकार प्रदान करती है-ऐसे प्राधिकरण-क्या इसमें मुकदमे के निर्णय के बाद अपील दायर करना शामिल है ट्रायल कोर्ट द्वारा - अपील के लिए नया संकल्प - यदि आवश्यक हो।

माना गया कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 6 में 'अवसर के लिए' शब्द महत्वपूर्ण हैं। जबकि एक पंजीकृत सोसायटी के स्थायी नियमों और विनियमों के तहत, सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव या किसी ट्रस्टी पर सोसायटी की ओर से मुकदमा करने या मुकदमा दायर करने के लिए एक सामान्य अधिकार से इनकार किया जा सकता है, एक संकल्प के माध्यम से दिया गया अधिकार शासी निकाय को संबंधित "अवसर" तक सीमित रखना होगा। अंतर बताने में, विधायिका का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि पंजीकृत सोसायटी को अनावश्यक और अंतहीन मुकदमेबाजी नहीं करनी चाहिए, अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए और सोसायटी के धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें मुकदमे के प्रत्येक विशिष्ट चरण में स्थिति का जायजा लेना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि मामले को आगे बढ़ाना उचित होगा या नहीं, यदि कोई पंजीकृत सोसायटी अपने अध्यक्ष और सचिव को उनकी ओर से मुकदमा दायर करने का अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव पारित करती है। सोसायटी, उस प्राधिकारी को, अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के मद्देनजर, उस मुकदमे में डिक्री से अपील दायर करने के लिए एक प्राधिकारी को शामिल करने के लिए नहीं समझा जा सकता है। ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे के फैसले के बाद, सोसायटी को स्थिति की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करना होगा और फिर एक और प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसमें सचिव या उसके अध्यक्ष को उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

(पैरा 7)

श्री सी.एस. तिवाना, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला की अदालत के 6 फरवरी 1967 के फैसले और डिक्री से नियमित दूसरी अपील, जो श्री एम.एस. नागरा, उप-न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, जगाधरी, दिनांक 31 जनवरी, 1966 की पुष्टि करती है

अपीलकर्ता की ओर से एम. पी. मालेरी,
एच. एल. सोनी, वकील, उत्तरदाताओं संख्या 8 और 9 के लिए

निर्णय

न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया,

आर.एस.ए. 1967 का 290, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के दिनांक 6 फरवरी, 1967 के एक आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 3, के तहत वादी की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह वादी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति, अर्थात् जगाधरी स्थित मंदिर में स्थापित मूर्ति श्री रघुनाथ जी द्वारा दायर नहीं किया गया था। यह निम्नलिखित तथ्यों से उत्पन्न होता है:

2. जगाधरी के मंदिर में स्थापित मूर्ति श्री रघुनाथ जी ने शाश्वत निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक को प्रतिवादी संख्या 8 (डी.ए.वी. कॉलेज प्रबंध समिति) और प्रतिवादी संख्या 9 (श्री) को वाद-संपत्ति का कब्जा हस्तांतरित करने से रोका गया। राम लाल, हेडमास्टर, जी.एस.ए.एस. हाई स्कूल, यमुनानगर) और प्रतिवादी 8 और 9 को वाद-संपत्ति के कब्जे में प्रवेश करने और उस पर निर्माण करने से रोकने के लिए भी। अधीनस्थ न्यायाधीश, जगाधरी ने प्रतिवादी 1 से 4, 8 और 9 के खिलाफ मुकदमे का आंशिक फैसला सुनाया, लेकिन प्रतिवादी 5 से 7 के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया। उस फैसले के खिलाफ, वादी जिला न्यायाधीश के पास अपील में गया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी, कि अपील ठीक से दायर नहीं की गई थी, क्योंकि यह वादी या श्री धर्म अस्थान समिति द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दायर नहीं की गई थी, जो वादी की ओर से मोहतमिम के रूप में कार्य कर रहा था। . यह आपत्ति अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास पहुंची, जिसके परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी गई। अतः अपर जिला न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील है।

3. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील का तर्क है कि मुकदमे में वादी पर श्री धर्म अस्थान समिति के अध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्होंने श्री द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में वादी के लिए वकील के रूप में श्री लक्ष्मी चंद को नियुक्त किया था। धर्म अस्थान समिति के अध्यक्ष डॉ.रामेश्वर दास और समिति के सचिव श्री बृज लाल ने वकील श्री लक्ष्मी चंद के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर किए थे, जो इसके तहत जिला न्यायाधीश के पास अपील दायर करने के लिए अधिकृत थे। इस बात पर जोर दिया गया है कि अपील केवल मूल मुकदमे की निरंतरता थी, और समिति द्वारा 21 अक्टूबर, 1964 के संकल्प के अनुसार दिए गए अधिकार में ट्रायल कोर्ट के किसी भी प्रतिकूल निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार शामिल होगा। इस प्रकार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 21) (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 6 की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन किया गया था। यह आगे बताया गया है कि आदेश 41, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान विवेकाधीन हैं, जैसा कि "हो सकता है" शब्द से संकेत मिलता है, और इन परिस्थितियों में, जब अपील के ज्ञापन पर श्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे लक्ष्मी चंद, अधिवक्ता, जो समिति के विधिवत गठित वकील थे, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को अपील को खारिज नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपील के ज्ञापन में दोष, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए अपीलकर्ता को अतिरिक्त समय देना चाहिए था। अपने तर्क के समर्थन में, श्री एम. पी. मालेरी ने लोहकु और अन्य बनाम भोला राम का उल्लेख किया है। .

4. जवाब में, प्रतिवादी-प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री एच.एल. सोनी ने तर्क दिया कि यद्यपि श्री धर्म अस्थान समिति को मुकदमा दायर करने के लिए अधिकृत करने वाले प्रस्ताव को वादी के पैरा 12 में संदर्भित किया गया है, वादी में लगाया गया यह आरोप गलत था। स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन प्रतिवादियों 4, 5, 6, और 7 ने अपने लिखित बयानों में इसका खंडन किया। प्रतिवादी संख्या 8 (डी.ए.वी. हाई स्कूल) ने अपने लिखित बयान में एक विशिष्ट आपत्ति उठाई कि श्री धर्म अस्थान समिति के पास मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। परिणामस्वरूप, इस बिंदु पर एक मुद्दा तैयार किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमा दायर करने वाले अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर दास और सचिव श्री बृज लाल के अधिकार को चुनौती दी जा रही थी, यह दस्तावेज़, जो समिति के संकल्प की प्रतिलिपि होने का दावा करता है, कभी नहीं किया गया था। डॉ.रामेश्वर दास के साक्ष्य में साबित या संदर्भित किया गया, जो पी.डब्ल्यू. के रूप में सामने आए। 2. श्री सोनी ने इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि इस प्रस्ताव का उल्लेख कभी भी ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायाधीश के समक्ष बहस के समय भी नहीं किया गया था। न ही इस न्यायालय में दायर अपील के आधारों में इसका उल्लेख किया गया है। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के वकील श्री सोनी को इस अप्रमाणित दस्तावेज़ को संदर्भित करने और उस पर अपना तर्क बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विकल्प में, श्री सोनी का तर्क है कि भले ही उपरोक्त प्रस्ताव को डॉ. रामेश्वर दास और श्री बृज लाल को मुकदमा दायर करने के लिए दिए गए अधिकार के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे उन्हें अपील दायर करने का अधिकार देने के रूप में नहीं

माना जा सकता है, क्योंकि इसका सीधा सा कारण यह है कि अपील मुकदमे की अगली कड़ी नहीं थी। सोसायटी के किसी भी उपनियम या विनियमन के अभाव में, अपील दायर करने के लिए विशेष रूप से डॉ. रामेश्वर दास या श्री बृज लाल या यहां तक कि श्री लक्ष्मी चंद, वकील को अधिकृत करने वाले एक नए प्रस्ताव से कम कुछ भी धारा 6 के मद्देनजर पर्याप्त नहीं था। अधिनियम का. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और अन्य में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा किया है। वी. मेसर्स वालिया ब्रदर्स, बनूर रोड, खरड़, जिला अम्बाला आईएलआर (1968) 2 पी एंड एच। 250, पी. सी. पंडित द्वारा, जे.

5. यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस दस्तावेज़ को श्री मालेरी सोसायटी के शासी निकाय के संकल्प के रूप में संदर्भित करते हैं, वह इस तथ्य के बावजूद कभी साबित नहीं हुआ या यहां तक कि सबूत के रूप में संदर्भित नहीं किया गया, अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर दास का अधिकार था। और श्री बृज लाल, सचिव से प्रतिवादियों द्वारा दलीलों में पूछताछ की गई और उस बिंदु पर एक मुद्दा तैयार किया गया। श्री मालेरी के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि जिस समय इस दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था उस समय कोई आपत्ति नहीं की गई थी। वास्तव में, यह दस्तावेज़ कभी भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। आपत्ति को कभी नहीं छोड़ा गया। एक मुद्दे को मुद्दे पर दबा दिया गया. नतीजतन, अपीलकर्ता उस दस्तावेज़ पर भरोसा नहीं कर सकता है और उस अप्रमाणित दस्तावेज़ पर तर्क नहीं दे सकता है।

6. यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि विधिवत प्रमाणित न होने के बावजूद इस दस्तावेज़ पर विचार किया जा सकता है, तो भी यह अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा, जो इस प्रकार है इस प्रकार है:

6. समाजों द्वारा और उनके विरुद्ध मुकदमा

इस अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक सोसायटी अध्यक्ष, अध्यक्ष, या प्रधान, सचिव, या ट्रस्टियों के नाम पर मुकदमा कर सकती है या मुकदमा दायर कर सकती है, जैसा कि सोसायटी के नियमों और विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और, इस तरह के निर्धारण में डिफ़ॉल्ट होने पर, ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे इस अवसर के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

उसे उपलब्ध कराया....

7. धारा 6 में अवसर के लिए "शब्द महत्वपूर्ण हैं। जबकि सोसायटी के स्थायी नियमों और विनियमों के तहत, सोसायटी की ओर से मुकदमा करने या मुकदमा दायर करने के लिए सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव या किसी ट्रस्टी को एक सामान्य अधिकार प्रदान किया जा सकता है, एक संकल्प के माध्यम से

दिया गया अधिकार शासी निकाय को संबंधित "अवसर" तक सीमित रहना होगा। अंतर बताने में विधायिका का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि पंजीकृत सोसाइटियों को अनावश्यक और अंतहीन मुकदमेबाजी नहीं करनी चाहिए, अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए और सोसायटियों के धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें मुकदमेबाजी के प्रत्येक विशिष्ट चरण में स्थिति का जायजा लेना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि मामले को आगे बढ़ाना उचित होगा या नहीं। इस प्रकार, भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि श्री धर्म अस्थान समिति के शासी निकाय ने एक प्रस्ताव पारित करके अपने अध्यक्ष और सचिव को मुकदमा दायर करने के लिए अधिकृत किया था, फिर भी उपरोक्त के मद्देनजर उस अधिकार को नहीं माना जा सकता है अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार शामिल है, जो काफी हद तक सोसायटी के पक्ष में था। यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे के फैसले के बाद, सोसाइटी ने स्थिति की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन किया और फिर एक और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सचिव या उसके अध्यक्ष को उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए अधिकृत किया गया।

8. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के मामले (2) में, मेसर्स वालिया ब्रदर्स ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय पर रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। ब्याज सहित 3,20,000 रु. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, यह आपत्ति उठाई गई थी कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना एक कॉर्पोरेट निकाय है, इसकी कार्यवाही इसके प्रबंधन बोर्ड के प्रस्तावों द्वारा संचालित की जाती है, और चूंकि बोर्ड ने इस आशय का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत करते हुए एक अपील दायर की जानी चाहिए, अपील ठीक से स्थापित नहीं की गई थी और इस आधार पर खारिज की जा सकती थी। विश्वविद्यालय के वकील ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1961 की धारा 12(2) के तहत कुलपति की शक्तियों और विश्वविद्यालय के पृष्ठ 109 पर दिए गए अनुसूची भाग "बी" में आइटम नंबर 27 का हवाला दिया। 1967-68 का अधिनियम और क़ानून। धारा 12(2) में, यह उल्लेख किया गया है कि कुलपति विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। इस तर्क से निपटते हुए पी.सी. पंडित, जे. ने पाया कि विश्वविद्यालय के वकील द्वारा संदर्भित प्रावधानों ने कुलपति को अपील शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं किया। यह भी माना गया कि आइटम नंबर 27 भी, जो कुलपति को संबंध में व्यय स्वीकृत करने का अधिकार देता है। "कुलपति की मंजूरी से" शुरू किए गए सिविल मुकदमों के साथ, कुलपति को कोई विशेष मुकदमा, या अपील दायर करने के लिए कोई शक्ति या अधिकार प्रदान नहीं किया गया, और यह बोर्ड के एक प्रस्ताव से कम नहीं है। प्रबंधन, कुलपति को अपील दायर करने के लिए अधिकृत करते हुए, इस उद्देश्य के लिए एक वैध प्राधिकारी का गठन करेगा।

9. उच्चतम न्यायालय ने कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय और अन्य बनाम में अपना आधिपत्य कायम रखा है। एस.के. घोष और अन्य, (एक निर्णय जिसे संदर्भित किया गया है। पंजाब कृषि

विश्वविद्यालय के मामले में, (2) कि हालांकि एक विश्वविद्यालय की तरह एक निगमित निकाय, एक कानूनी इकाई थी, लेकिन इसमें न तो कोई जीवित दिमाग था और न ही आवाज। यह केवल एक औपचारिक संकल्प द्वारा औपचारिक तरीके से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है और इसलिए अपने संविधान द्वारा निर्धारित तरीके से उचित रूप से विचार किए जाने, पारित किए जाने और विधिवत दर्ज किए गए संकल्प के माध्यम से ही अपनी कॉर्पोरेट क्षमता में कार्य कर सकता है। यही नियम लाहौर हाई द्वारा निर्धारित किया गया था एआईआर 1943 318 (लाहौर) में न्यायालय।

10. मुझे इस तर्क से कोई आपत्ति नहीं है कि आदेश 41, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान विवेकाधीन हैं, जैसा कि "हो सकता है" शब्द से संकेत मिलता है। लेकिन मामले की परिस्थितियों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह संकेत मिले कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा इस विवेक का गलत प्रयोग किया गया था। परिणाम यह हुआ कि अपील विफल हो गई और इसे खारिज कर दिया गया। मामले की परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा